स्कूटर के धुएं की जांच करके दिखाओ पीयूसी यूनिट काम कर रही है या नहीं

पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव ने देखी वाहनों के प्रदूषण जांचने की व्यवस्था

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

अरे...भाई ये पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) यूनिट ठीक से काम कर रही है। जी सर, बिल्कुल ठीक चल रही है। अच्छा, सड़क पर आ रही स्कूटर को रोको और प्रदूषण की जांच करके दिखाओ। पीयूसी ऑपरेटर ने एक स्कूटर को रुकवाया और जांच की। इसमें स्कूटर के धुएं में प्रदूषण का स्तर मानक से अधिक पाया गया। यह वाक्या गुरुवार सुबह 11.15 बजे शाहपुरा स्थिति पर्यावरण परिसर में हुआ।

दरअसल, पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दफ्तर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें पीयूसी वैन खड़ी दिखाई दी। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और पीयूसी के ऑपरेटर से पूछताछ की। साथ ही यूनिट की जांच भी की।

इस दौरान उन्होंने सबसे पहले जिस स्कूटर को रोककर जांच कराई थी, उसमें कार्बन मोनो आक्साइड का स्तर 4.5 प्रतिशत से अधिक निकला। इस पर प्रमुख सचिव संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने एक और बाइक को रुकवाकर जांच कराई। इस बाइक के धुएं में कार्बन मोनो आक्साइड का स्तर 4.5 प्रतिशत से कम पाया गया, तब जाकर वे संतुष्ट हुए। प्रमुख सचिव ने स्कूटर चालक से कहा कि आप वाहन की ठीक से सर्विसिंग कराएं और प्रदूषण नियंत्रण में मदद करें। इस पर उसने सहमति जताई।

शाहपुरा में वाहनों को रुकवाकर पीयूसी वैन से करवाई जांच

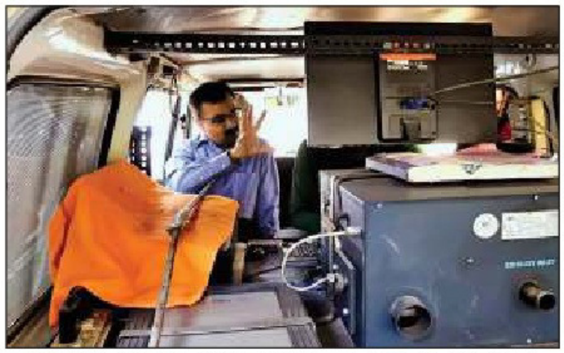

शाहपुरा स्थिति पर्यावरण परिसर में पीयूसी वैन के उपकरणों की जांच करते पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन।

एनजीटी ने हाल ही में दिए थे पीयूसी यूनिटों की जांच के निर्देश

एनजीटी ने हाल ही में पीयूसी द्वारा वाहनों को दिए जा रहे प्रदूषण जांच प्रमाण पत्रों पर सवाल उठाए थे। एनजीटी ने कहा था कि प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों को देखना चाहिए कि पीयूसी द्वारा वाहनों को जो जांच प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, इसमें कोई खामी तो नहीं है। इसके बाद से मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सख्त है। सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पीयूसी की निगरानी करें। साथ ही अधिक से अधिक वाहनों को जांच के दायरे में लाएं। इसी के चलते पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव ने गुरुवार को जांच की। उनके साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एए मिश्रा भी मौजूद थे।

ये है पीयूसी

यह प्रदूषण अंडर कंट्रोल यूनिट है। इसके माध्यम से दो और चार पहिया वाहनों के धुएं की जांच की जाती है। जांच में पता चलता है कि वाहन से जो धुआं निकल रहा है, उसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषित कारकों का स्तर तय सीमा से अधिक तो नहीं है। जांच के बाद ये पीयूसी यूनिट वाहन मालिकों को प्रमाण पत्र देती है कि उनकी गाड़ी प्रदूषण नहीं फैलाती।

बैठक में निर्णय • तय सीमा से अधिक आवाज के पटाखे मिले तो लाइसेंस सस्पेंड

100 से ज्यादा पटाखों वाली लड़ियों पर बैन

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

कलेक्टोरेट में मंगलवार को पटाखा व्यापारियों के साथ जिला प्रशासन, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों ने बैठक की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पटाखे बेचने के दिशा-निर्देशों पर व्यापारियों से चर्चा करने के लिए बैठक रखी गई। बैठक शुरू होते ही व्यापारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। कलेक्टर सुदाम खाडे को बताया कि व्यापारियों द्वारा करीब 6 करोड़ रुपए के पटाखे खरीद लिए गए हैं। कंपनियों के पास ग्रीन पटाखे मौजूद नहीं थे। मजबूरी में जो पटाखे का स्टॉक उपलब्ध है, वो ही बेच पाएंगे। इस पर कलेक्टर खाडे ने कहा कि बिना लेबल के रस्सी बम बेचे तो दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। 100 से ज्यादा पटाखों वाली लड़ियां बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया है।

कलेक्टर ने प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी पीएस बुंदेला से सवाल किया कि रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर क्या करोगे? बुंदेला ने कहा कि क्या कार्रवाई करेंगे यह स्पष्ट नहीं है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि आम लोगों में टाइमिंग को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। शहर में 15 से ज्यादा पटाखे के थोक विक्रेता हैं। इनके द्वारा शहरभर में पटाखे सप्लाई किए जाते हैं। बुंदेला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पटाखा दुकानों पर ग्रीन पटाखे बेचे जाएं। इसके साथ पटाखों का ध्वनि लेवल 125 डेसीबल से अधिक नहीं होना चाहिए। इस पर कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम की टीम पटाखा दुकानों की जांच करेगी। किसी भी दुकान पर तय लेवल से अधिक ध्वनि के पटाखे मिलने पर दुकान को सील कर लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।

व्यापारी ने पूछा- क्या होता है ग्रीन पटाखा

पटाखा व्यापारी प्रसन्न कुमार ने सवाल किया कि यह ग्रीन पटाखा क्या होता है? इस पर प्रदूषण बोर्ड के वैज्ञानिक ने बताया कि बिना कैमिकल पोल्यूशन, लीथियम और बिना मर्करी वाले पटाखे ग्रीन पटाखे कहलाते हैं।

1 नवंबर से जागरूकता अभियान

कलेक्टर ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 नवंबर से होगी। प्रचार-प्रसार के लिए एलईडी, होर्डिंग्स लगाएं। रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने वालों पर कार्रवाई को लेकर कलेक्टर कुछ नहीं बोले।

एडवाइजरी जारी : • पटाखे जलाने के लिए मोमबत्ती या अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। • पटाखे जलाने के दौरान पास में पानी रखें। • खराब या अध जले पटाखों को पानी में डुबो दें।

गणेशोत्सव में विसर्जन से खराब हो गई थी नदी, इस बार समेल्याचाऊ के ग्रामीणों ने संभाल लिया मोर्चा

शिप्रा को बचाने लाठी लेकर खड़ा हो गया गांव, नहीं विसर्जित करने दी प्रतिमाएं

अपनी नदी, अपनी मां शिप्रा को बचाने सेमल्या चाऊ ने इस बार लाठी उठा ली। शिप्रा के बेटे सुबह से नदी के बाहर मोर्चा संभालकर बैठ गए। प्रतिमा विसर्जित करने आए लोगों को किनारों पर रोक कर प्रतिमाएं वहीं रखवा ली।

पूरे दिन चलाया सफाई अभियान

लोग यहीं तक नहीं रुके। पूरे दिन नदी सफाई अभियान चलाया। गणेशोत्सव के दौरान विसर्जित प्रतिमाओं के अवशेष बाहर निकाले। निर्माल्य हटाए और गाद निकाली। लोगों को चिंता इस बात की है कि इस बार कम बारिश होने से वैसे ही नदी में कम पानी है। वह भी गंदी हो गई तो बाकी के दिन पानी का इंतजाम दूभर हो जाएगा।

इंदौर. ग्राम सेमल्याचाऊ में दशहरे पर लोगों ने अनूठा अभियान चलाया। नर्मदा-शिप्रा संगम पर नदी को बचाने के लिए गांव वाले डंडा लेकर खड़े हो गए। यहां नदी में माता की प्रतिमाएं विसर्जित करने पहुंचे लोगों को रोक दिया और प्रतिमाओं को किनारों पर ही रखवा लिया। किसी ने हुज्जत करने की कोशिश की तो उसे डंडा दिखाकर समझा दिया, हालांकि ज्यादातर आसानी से मान गए। अब इन प्रतिमाओं को गांव वाले ही दूसरी जगह ले जाकर विसर्जित करेंगे। इस बार हुई कम बारिश ने नदी का जलस्तर काफी कम कर दिया है, पानी भी काफी गंदा भी हो गया है। ग्रामीण पुलकित चौहान ने बताया, गणेश विसर्जन के दौरान लोगों ने ग्रामीणों के विरोध के बाद भी यहां प्रतिमाएं विसर्जित कर दी थीं। हालांकि उस समय नदी में काफी पानी था। अब पानी घटने के साथ भगवान गणेश की तब विसर्जित कई प्रतिमाएं बाहर नजर आने लगी हैं। इस कारण अब देवी प्रतिमाएं यहां विसर्जित की जातीं तो वे डूबती भी नहीं। इस कारण ग्रामीणों ने तय किया कि वे नदी में प्रतिमा विसर्जित नहीं होने देंगे। इसे रोकने के लिए चौहान के साथ शिवम सोनी, प्रदीप जाट, रमेश पटेल, शुभम पटेल आदि ने सुबह से ही घाट डंडा लेकर पर मोर्चा संभाल लिया। जब भी लोग प्रतिमाएं लेकर आए तो उन्हें विसर्जित नहीं करने दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इन प्रतिमाओं को नदी के बजाए किसी गड्ढे के पानी में विसर्जित कर देंगे, ताकि नदी स्वच्छ रहे। नदी में जमा गंदगी को साफ करने का अभियान भी ग्रामीणों ने शुरू किया।

नदी से सिंचाई के कारण पानी हुआ कम

ग्रामीणों का कहना है, आसपास के लोग सीधे नदी में मोटर लगाकर अपने खेतों में पानी ले जा रहे है, इससे नदी का जलस्तर काफी कम हो गया है।

नदी के बेटों का भगीरथी प्रयास

पूर्व में विसर्जित प्रतिमाओं के अवशेष निकाले।

निर्माल्य हटाए, गाद निकालकर की सफाई।

दैनिक भास्कर - 20-10-18

उज्जैन

कार्रवाई • अमले ने की शुरुआत, विभिन्न दुकानों से 150 किलो पॉलीथिन जब्त, आठ हजार का जुर्माना लगाया

सात दिन में महाकाल, गोपाल मंदिर और छत्रीचौक क्षेत्र को पॉलीथिन फ्री बनाने का निगम का दावा

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

सात दिन में महाकाल, गोपाल मंदिर और छत्रीचौक क्षेत्र को पॉलीथिन फ्री बनाया जाएगा। निगम अमले ने शुक्रवार को इसकी शुरुआत कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की अगुवाई में हुई कार्रवाई के तहत विभिन्न क्षेत्रों से 150 किलो पॉलीथिन जब्त की। साथ ही आठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के अनुसार पॉलीथिन उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाकाल, गोपाल मंदिर, छत्रीचौक और आस-पास के क्षेत्रों को एक सप्ताह में पॉलीथिन फ्री कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा- यह अधिकारियों और कर्मचारियों के लचर रवैए का ही नतीजा है प्रतिबंध के बावजूद शहर में पॉलीथिन की खरीद-फरोख्त हो रही है। साथ ही बाजार में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई की संबंधित अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि किसी भी क्षेत्र में पॉलीथिन पर प्रतिबंध दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा-प्रतिबंध का पालन नहीं कराने वाले अफसरों-कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है नगर निगम क्षेत्र में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। पहले चरण में महाकाल, गोपाल मंदिर, छत्रीचौक और आस-पास के क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह में इन क्षेत्रों को शत-प्रतिशत पॉलीथिन फ्री कर दिया जाए। जिन व्यवसायियों के यहां अमानक स्तर की पॉलीथिन का उपयोग किया जाएगा वहां पर छापामार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। शुक्रवार को स्वास्थ्य अमले ने कार्रवाई करते हुए गोपाल मंदिर, छत्रीचौक क्षेत्रों से 150 किलो पॉलीथिन जप्त की। साथ ही आठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कार्रवाई में स्वास्थ्य अधिकारी पुरुषोत्तम दुबे के साथ स्वास्थ्य निरीक्षक विक्रमसिंह पंड्या मौजूद थे।

पुलिस का सहयोग लेंगे, बाहर से शहर में आने वाले हर ट्रक को जांचेंगे

पॉलीथिन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए निगम पुलिस का सहयोग भी लेगा। उपायुक्त योगेंद्र पटेल ने बताया शहर में आने वाली पॉलीथिन को ही रोकने का काम करेंगे। इस क्रम में पुलिस से आग्रह किया जाएगा कि वह नगर सीमा में आने वाले हर ट्रक की जांच करें। साथ ही पॉलीथिन पाए जाने पर वहीं जप्त कर लें। इसी तरह पॉलीथिन के बड़े स्टॉकिस्टों के यहां छापामार कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के साथ निगम के बाजार वसूली में लगे अमले को भी निर्देश दिए जाएंगे कि वह शहर में कहां-कहां पॉलीथिन की बिक्री हो रही है, इस पर नजर रखें।

अवकाश के दिन कार्रवाई, डेढ़ क्विंटल पॉलीथिन जब्त

निगमायुक्त ने कहा-एक सप्ताह में शहर को पॉलीथिन मुक्त कराएंगे, व्यवसाइयों पर 8 हजार जुर्माना ठोंका

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

पुराने शहर के विभिन्न क्षेत्र की दुकानों से निगम टीम ने पॉलीथिन जब्त की।

उज्जैन. दशहरा अवकाश के दिन ही नगर निगम टीम पॉलीथिन जब्ती की कार्रवाई के लिए निकल पड़ी। गोपाल मंदिर, छत्री चौक, ढाबा रोड सहित आसपास टीम ने दुकानों पर चेकिंग की और डेढ़ क्विंटल पॉलीथिन जब्ती में लेते हुए व्यापारियों से 8 हजार रुपए का अर्थदंड वसूला। त्योहार के दिन इस तरह की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में कुछ रोष भी रहा, लेकिन स्थायी आदेश के पालन का उल्लंघन होने पर किसी ने खुलकर विरोध नहीं किया।

निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने निगम स्वास्थ्य अमले को निर्देशित किया कि जब शहर में पॉलीथिन प्रतिबंधित है तो फिर क्यों खुलेआम सभी जगह इसका उपयोग होता है। निगम के नरम व लचीले रवैए के कारण ही विक्रेताओं में भय नहीं रहता। उन्होंने एक सप्ताह में शहर के सभी क्षेत्रों को पॉलीथिन मुक्त बनाने के निर्देश दिए। यानी अब निगम निरंतर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देगा। बता दें, शहर में पॉलीथिन बैग के उपयोग पर रोक है, बावजूद सभी दुकानों पर अमानक स्तर की पॉलीथिन उपयोग में लाई जाती है।

दैनिक जागरण दि: 05 अक्टूबर 2018

राजधानी सहित प्रदेश के चार शहरों में लगेंगी एयर क्वालिटी मशीन, प्रदेश के पांच शहरों में शुरू हुई प्रक्रिया

तुरंत देख सकेंगे कितनी प्रदूषित है आपके क्षेत्र की हवा

नगर संवाददाता, भोपाल

शहर की हवा कैसी है, उसमें कितना प्रदूषण है, इसका पता अब तत्काल चल जाएगा। इसके लिए मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल्द ही कंटीन्यूअस एंबिएंट एयर क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम लगाएगा। यह सिस्टम अभी राजधानी में एक स्थान पर लगाया जाएगा। इसके साथ ही जबलपुर, ग्वालियर सहित अन्य शहरों में भी इस तरह के सिस्टम लगाए जाएंगे। यह मशीन राजधानी के न्यू मार्केट, एमपी नगर या पुराने शहर में से किसी एक स्थान पर लगाई जा सकती है। सिस्टम लगने के बाद हर पल हवा की गुणवत्ता जांचने के साथ ही इसे डिस्प्ले बोर्ड पर लगाकर सार्वजनिक किया जाएगा। इससे शहरवासियों को रोजाना प्रदूषण की स्थिति का पता चलेगा। हवा में प्रदूषण फैलाने वाले कौन-कौन से कारक हैं, इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। इससे प्रदूषण को कम करने के उपाय भी खोजे जाएंगे। हवा की गुणवत्ता की यह जानकारी रोजाना लोग पीसीबी की वेबसाइट पर भी देख सकेंगे। वेबसाइट पर इसकी जानकारी अपडेट होती रहेगी। इस सिस्टम को लगाए जाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आर्डर भी दे दिया है।

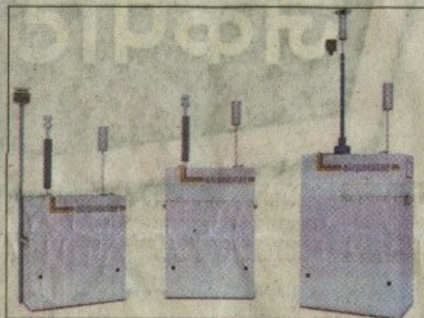

यहां लगाई जाएंगी मशीन : भोपाल के एयरपोर्ट रोड, अपेक्स बैंक चौराहा, एमपी नगर, कोलार रोड में से किसी एक स्थान पर यह मशीन लगाए जा सकती है। इसके अलावा ग्वालियर में जीवाजी विवि के पास मशीन लगाई जाएगी। जबलपुर में नगर निगम दफ्तर या डीआरएम ऑफिस के पास यह मशीन लगाई जा सकती है।

80 लाख की मशीन

हवा की क्वालिटी जांचने वाली यह मशीन करीब 80 लाख रुपए की है। जो कंपनी इस सिस्टम को लगाएगी, उसे सात साल तक इस सिस्टम का मेंटेनेंस भी करना होगा।

अभी 15 दिन में आ रही है रिपोर्ट

अभी सतत निगरानी वाले पांच शहरों को छोड़कर अन्य जिलों की वायु प्रदूषण रिपोर्ट हर 15 दिन में आ रही है। इस तरह की रिपोर्ट राजधानी के छह स्थानों की आती है। इनमें पर्यावरण परिसर, गोविंदपुरा, कोलार, होशंगाबाद रोड, बैरागढ़ और सिविल अस्पताल क्षेत्र शामिल हैं।

दस लाख की आबादी वाले शहरों के लिए सिस्टम

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रदूषण की सतत निगरानी के लिए सीएएक्यूएमएस बनाया है। मप्र में यह सिस्टम दो साल पहले ही लगाया जाना था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के फंड के चक्कर में यह योजना आगे नहीं बढ़ पा रही थी।

पांच शहरों में शुरू हो चुकी है सतत निगरानी

हवा को जांचने की सतत निगरानी अभी प्रदेश के पांच शहरों में शुरू हो चुकी है। इनमें देवास, उज्जैन, पीतमपुर, सिंगरौली और मंडीदीप शामिल हैं। इन शहरों की हवा की गुणवत्ता वेबसाइट पर जाकर रोजाना देखी जा सकती है।

हवा की क्वालिटी जांचने के लिए सिस्टम जल्द लग जाएगा। इसके लिए आर्डर भी दिए जा चुके हैं। इससे लोगों को तुरंत हवा के प्रदूषण की जानकारी मिल जाएगी।

डॉ. रीता कोरी
चीफ वैज्ञानिक, पीसीबी

तीन स्तर पर तालाबों का प्रदूषण मापेगा नियंत्रण बोर्ड

इंदौर। अनंत चतुर्दशी पर शहर के जलाशयों में मूर्ति विसर्जन रोकने के लिए नगर निगम की टीम तैनात रहेगी। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम इस बार तीन स्तर पर जलाशयों में प्रदूषण की स्थिति मापेगी। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक हर साल नगर निगम के साथ मिलकर प्लान बनाया जाता है। इस बार भी शहर में 100 से अधिक पर्यावरण हितैषी जलकुंड बनाए जाएंगे, जिनमें मूर्तियां विसर्जित की जाएंगी। विसर्जन के दिन नगर निगम की टीम बिलावली, यशवंत सागर, पीपल्याराव तालाब पर मौजूद रहेगी और लोगों को मूर्ति विसर्जन करने से रोकेगी। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि हम लोग इस बार तीन स्तर पर तालाबों का सैंपल लेंगे। एक बार सैंपल ले लिया है। विसर्जन वाले दिन भी सैंपल लिया जाएगा और फिर विसर्जन के एक सप्ताह बाद लिया जाएगा। इसके बाद इसकी तुलना की जाएगी। पिछले साल जवाहर टेकरी पर कृत्रिम कुंड का भी सैंपल लिया गया था, जिसमें बड़ी मात्रा में प्रदूषक और ठोस तत्व पाए गए थे। -नप्र

SOYAMEAL EXPORTERS CHEER AS CHINA MULLS LIFTING OF BAN | 3

Narmada water Swachh & drinkable

Reveal Tests By Pollution Control Board

Times News Network

Indore: The water of Narmada is drinkable and good for aquatic life, revealed examination of samples taken recently by regional Pollution Control Board (PCB).

As per report of the laboratory examination by regional PCB, Narmada water has fallen under top A grade, which makes it suitable for drinking without conventional treatment but after disinfection.

The board had taken water samples from 17 different locations on Narmada as part of pre, during and post monitoring of water bodies ahead of idol immersion taking place during Ganeshotsav. Dr DK Wagela, chief chemist and lab head at regional PCB said, "The water quality of Narmada is very good and suitable for aquatic life. The water was clear and less muddy." Wagela said the water quality has improved due to better condition of nullahs and prevention of dirty water from getting mixed into river.

According to the board sewage treatment plants have also helped in improving quality of water.

The board also collected samples from 10 tributaries of Narmada. Water samples are regularly been taken from different spots as part of the guidelines issued by Central PCB to monitor water quality before, during and post idol immersion.

The administration has restricted immersion of idols in lakes, rivers and ponds to prevent pollution.

According to the guidelines, the board is monitoring the levels of pH, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, total dissolved solids, conductivity, turbidity, chromium, lead, zinc and copper.

RESULTS OF NARMADA WATER ANALYSIS

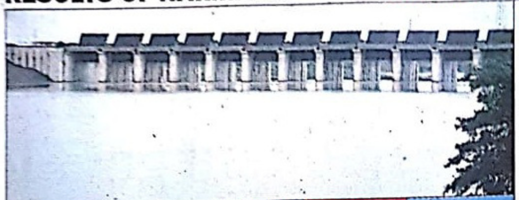

CHARACTERISTICS	RESULT	STANDARD	UNIT
D Oxygen	7.11	6 or more	mg/1
BOD	1.19	2 or less	mg/1
Total Coliform Organism	41.79	50 or less	MPN/100ml

Source Regional Pollution Control Board

"The water quality of Narmada is very good and suitable for aquatic life. The water was clear and less muddy. The quality has improved due to better condition of nullahs and prevention of dirty water from getting mixed into river. Sewage treatment plants have also helped in improving quality"

Dr DK Wagela | CHIEF CHEMIST AND LAB HEAD AT REGIONAL PCB

IMC staff told to

Pollution control board to monitor immersion effect

By Collecting Samples From Rivers And Ponds

TIMES NEWS NETWORK

Indore: As Ganesh Chaturthi is round the corner, the regional Pollution Control Board (PCB) has geared up to monitor pollution level of water bodies when thousands of lord Ganesh idols will be immersed.

> We will concentrate mostly on monitoring while IMC will look after the temporary ponds and other arrangements during the festival
>
> **Dr DK Wagela** | PCB CHIEF CHEMIST AND LAB HEAD

The PCB will collect water samples from rivers including, Narmada, Chambal, Gambhir, Choral, Tapti and Kunda and ponds of the region to examine the pollution levels.

PCB chief chemist and lab head Dr DK Wagela said, "We have selected multiple spots from where water samples will be collected. Directives have been received by us and accordingly we have chalked out the plans."

The board will take water samples from different sites before, during and after immersion of idols to check water contamination from idol immersion.

Over 10 parameters such as hardness, pH, and TDS levels will be checked by the board.

The board will also monitor water quality of Sirpur lake, Yeshwant Sagar, Bilawali pond, Pipliyapala and Jawahar Tekri.

Wagela said, "We will concentrate mostly on monitoring while IMC will look after the temporary ponds and other arrangements during the festival."

As per the directive of the pollution department, worship material like flowers, clothes, and decoration items should be removed before immersion of idols.

File pic.

IMC will set up ponds of 4x10 sqft acorss the city ahead of Ganesh Chaturthi. They will be made of plastic with inlet and outlet pipes.

100 ponds to be set up for immersion

Indore: Like every year, Indore Municipal Corporation (IMC) has started preparation to set up temporary ponds across the city for immersion of Ganesha idols.

IMC water works in charge Balram Verma said 100 ponds will be set up in all parts of the city. It will cost the civic body Rs12 lakh.

"The arrangement for artificial ponds will be the same as last year. In 2017, 80 ponds were set up across the city. This time we have decided to increase the number of the ponds by 20 based on the requirement," he said. The civic body would also set up centre to collect idols from areas, where temporary ponds will be built.

The ponds will be 4x10 sqft in size. They will be made of plastic with inlet and outlet pipes. "Reusable material will be used to protect environment. The ponds will have water of 11 holy rivers including, Narmada, Ganga and Godavari," Verma said. This time, the civic body will also seek help of 400 volunteers of Taalaab Sanrakshan Samiti for monitoring of idol immersion. TNN

गणेशोत्सव पर ईको फ्रेंडली मूर्तियों की बिक्री के लिए निगम 200 दुकानें बनाएगा

इंदौर | मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा मूर्तियों के विसर्जन व उससे होने वाले जल प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में किए गए जागरूकता कार्यक्रम में निगम ने जानकारी दी कि ईको फ्रेंडली मूर्ति बेचने के लिए वह 200 दुकानें बना रहा है। निगम द्वारा सौ विसर्जन कुंड अलग से बनाए जाएंगे। कार्यक्रम गुरुवार को प्रीतमलाल दुआ सभागृह में हुआ। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आरके गुप्ता ने कहा मूर्तियों के रंग में हानिकारक केमिकल होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल प्रदूषण होता है। इन्हें रोकने के लिए मिट्टी व अन्य ईको फ्रेंडली मटैरियल से ही मूर्तिया बनाई जाना चाहिए। मुख्य अतिथि कलेक्टर निशांत वरवड़े ने कहा सभी मूर्तिकार मिट्टी की प्रतिमाएं बनाकर विक्रय करें व इनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाए। पार्षद व जलकार्य समिति प्रभारी बलराम वर्मा, बोर्ड के डायरेक्टर पीके त्रिवेदी, दिल्ली के वैज्ञानिक अनिल रावत ने भी संबोधित किया। डीके वाघेला, केपी सोनी, अजय मिश्रा, अतुल कोटिया, अशोक रामावत उपस्थित थे। संचालन सुनील व्यास ने किया।

Sculptors making eco-friendly idols to get free stalls from IMC

TIMES NEWS NETWORK

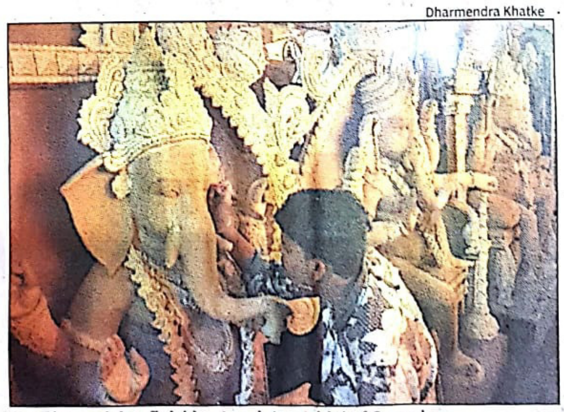

Dharmendra Khatke

A sculptor giving finishing touch to an idol of Ganesha

Indore: Ahead of Ganesh Chaturthi and Navratri, Indore Municipal Corporation will set up 200 stalls for sculptors making eco-friendly idols. The stalls will be given to them free of cost.

The state government has also proposed of giving loans to sculptors for making idols using nature friendly substances. These announcements were made on Thursday at an awareness programme and seminar conducted by the pollution control board on the side effects of idols, which are not eco-friendly.

The administrative and civic body officials told the sculptors and organisers about the ban on idols made using chemical substances or Plaster of Paris.

"All sculptors must only use clay and natural colours for making idols so that no legal action may be taken on them. The state is also ready to provide loans to those who are inclined to make eco-friendly idols for the coming festive season," collector Nishant Warwade said.

The IMC officials also reiterated the warning and ban on immersion of PoP idols in natural water bodies including ponds, lakes and rivers. IMC water works department head Balram Verma also told the audience about IMC's plan to set up shops of eco-friendly idols.

"These shops will be given free of cost to all sculptors selling idols made using eco-friendly material. The forms for these shops can be collected from the IMC office," Verma said.

He also spoke about the 100 ponds, which will be made for idol immersion. These ponds will have water of 11 rivers and people will be allowed to immerse the idols customarily, he said.

Central Pollution Control Board (CPCB) scientist at Delhi, Anil Rawat, spoke about the guidelines issued by the CPCB regarding idol immersion and advised people to immerse idols after removing flowers, clothes and decoration items from them.

The seminar saw participation of over 140 sculptors from the city along with NGO activists, representatives of utsav mandals, students, IMC officials, administrative officials and experts from pollution control board.

TCS
द करंट स्टोरी

भोपाल, 12 से 18 सितंबर 2018 | https://www.thecurrentstory.com/epaper | वर्ष- 01, अंक- 33, पृष्ठ- 8, मूल्य- 2 रु.

पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वच्छता भी, पीसीबी कर रहा विचार...

अब खाली बोतलों और पाउच के भी मिलेंगे दाम

प्रवेश गौतम। भोपाल

यदि आप पानी पीने के बाद खाली बोतल और नमकीन, चिप्स आदि के पाउच सड़कों पर फेंक देते हैं, तो रुक जाइए। आपको इन्हीं खाली बोतलों और पाउच के दाम भी मिलने वाले हैं। इन्हें दुकान पर देने से आपको पैसे मिल सकते हैं। शायद आपको यह पढ़कर आश्चर्य लगे, पर यह सच हो सकता है। दरअसल मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :पीसीबीः इस नई योजना पर विचार कर रहा है। संभवतः अगले साल तक नए नियम लागू हो जाएं।

योजना के अनुसार, पानी की बोतल, नमकीन आदि बनाने वाली कंपनियां खाली बोतलें एवं पाउच वापस लेकर उनके दाम भी चुकाएंगी। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति दुकान में जाकर खाली बोतल दुकानदार को देता है तो उसे इसके लिए पैसे मिलेंगे। इसी प्रकार पाउच आदि के लिए भी दुकानदार को पैसे देने होंगे। कंपनियों को बोतलों आदि पर %बाय–बैक% के दाम भी लिखने पड़ेंगे। हालांकि अभी इस योजना पर विचार चल रहा है। लेकिन यदि इस योजना को लागू किया जाता है तो निश्चित ही इसके सकारात्मक प्रयास दिखेंगे। कंपनियां इन बोतलों और पाउच को अपने स्तर पर वैज्ञानिक तरीके से निपटान करेंगी।

कुछ समय पहले पानी, नमकीन आदि बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ पीसीबी ने एक बैठक की थी। इस बैठक में पीसीबी ने कंपनियों से इस समस्या से निपटने के सुझाव मांगे थे। कंपनियों को दिसंबर 2018 तक अपने प्लान व सुझाव देने हैं। इसमें कंपनियों को बताना होगा कि वह अपनी बोतलों, पाउच आदि को कैसे वापस लेकर उसका निपटान करेंगे। अभी कुछ कंपनियां अपने सुझाव लेकर सामने आई हैं, लेकिन उपयोगकर्ता खाली बोतलों आदि को वापस दुकान में देने के लिए प्रेरित हों, ऐसा कोई प्लान अभी सामने नहीं आया है। इसको लेकर पीसीबी ने अपना सुझाव दिया है कि जिस प्रकार उनकी गाड़ी दुकानों तक उनके उत्पाद पहुंचाती है, उसी गाड़ी में खाली बोतलें आदि वापस कंपनी तक पहुंचे, ताकि कचरे का सही तरीके से निपटान हो सके।

पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वच्छता भी

प्रदेश में प्रति दिन लगभग 300 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट निकलता है। यह आंकड़ें नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के आधार पर अनुमानित हैं। इस कचरे में से लगभग 70 प्रतिशत रिसायकल करने योग्य होता है, लेकिन शेष 30 प्रतिशत का निपटान नहीं हो पाता, जिनमें थर्मोकॉल आदि शामिल हैं। पीसीबी के अधिकारी एम एल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्लास्टिक वेस्ट में सबसे ज्यादा समस्या खाली पानी की बोतलों और खाद्य पदार्थों जैसे कि नमकीन, चिप्स आदि के खाली पाउच की है। अकसर इन्हीं की वजह से ज्यादा गंदगी होती है और रिसायकल करने योग्य वेस्ट में से लगभग 70 से 80 प्रतिशत ही रिसायकल के लिए पहुंच पाता है, शेष नदी, नालों, सड़कों में पड़ा रहता है। यदि इनको सही तरीके से कलेक्ट कर लिया जाए तो काफी हद तक प्रदूषण होने से रोका जा सकता है, साथ ही यह योजना शहरों आदि को स्वच्छ रखने में भी योगदान देगी।

योजना से जुड़ी खास बातें

- प्रदेश में लगभग 300 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन
- इसमें से केवल 70 प्रतिशत का हो सकता है रिसायकल
- 30 प्रतिशत हार्ड प्लास्टिक जैसे कि थर्मोकॉल
- रिसायकल वाले वेस्ट का केवल 70 से 80 प्रतिशत ही हो पाता है कलेक्ट
- शेष से होता है प्रदूषण और गंदगी
- पानी की बोतलों को ही बीनते हैं रैग पिकर्स
- खाली बोतलों के कबाड़ी देता है 25–30 रुपए प्रति किलो
- कंपनियों को लिखना होगा %बाय–बैक% कीमत
- प्रति बोतल लगभग 1 रुपए और प्रति पाउच लगभग 25 से 30 पैसे, पर चल रहा विचार
- योजना के बाद रैग पिकर्स कमा सकते हैं 45–50 रुपए प्रति किलो
- नमकीन, चिप्स, दूध आदि के पाउच भी बीनेंगे रैग पिकर्स
- इनके भी मिलेंगे दाम
- नदी नाले जाम नहीं होंगे
- पर्यावरण के साथ, स्वच्छता में भी मिलेगा योगदान

रैग पिकर्स को होगा फायदा

रैग पिकर्स यानि कि कचरा बीनने वालों को इस योजना से काफी हद तक फायदा होगा। सड़कों, नालों आदि के पास पड़ी खाली बोतलों को रैग पिकर्स उठाकर कबाड़ी को बेचते हैं। कबाड़ी वाले 25 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रैग पिकर्स को भुगतान करते हैं, जबकि कबाड़ी इसी को 35 से 40 रुपए प्रति किलो में बेचता है। लेकिन यदि यह योजना लागू हो जाती है तो रैग पिकर्स को प्रति किलो लगभग 40 से 50 रुपए तक मिल सकता है। वर्तमान में रैग पिकर्स केवल पानी की बोतलों को ही बीनते हैं लेकिन नमकीन आदि के पाउच वहीं छोड़ देते हैं। इस योजना के लागू होने से नमकीन आदि के खाली पाउच भी बीनने लगेंगे। इससे नालों, सड़कों आदि में कचरा कम दिखेगा। रैग पिकर्स कबाड़ी को खाली बोतलें बेचते हैं, जो सही तरीके से वेस्ट का निपटान नहीं करते। लेकिन यदि यह योजना लागू होती है तो रैग पिकर्स इन बोतलों आदि को पास की दुकान में बेच सकते हैं जिससे कचरे का सही तरीके से निपटान हो सकेगा। इससे न केवल उन्हें ज्यादा दाम मिलेगा बल्कि उनकी उन्नति भी होगी।

कार बिन में रखें कचरा

अकसर लोग गाड़ियों में पानी की खाली बोतल, नमकीन आदि के पाउच सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण और गंदगी फैलती है। लेकिन इस योजना के लागू होने से आप इन बोतलों आदि को अपनी कार के डस्टबिन -कार बिन- रखें और अगली दुकान पर उसे देकर पैसे प्राप्त कर सकते हैं। इससे कचरा भी नहीं होगा और आपको आर्थिक लाभ भी होगा।

ईपीआर के तहत अनिवार्य

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने एक मामले में सुनवाई करते हुए निर्देश दिए थे कि सभी निर्माताओं को उनके उत्पादन की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत वेस्ट वापस लेना अनिवार्य है। इसी के तहत पीसीबी इस योजना पर विचार कर रहा है।

> कंपनियों के लिए बाय–बैक पॉलिसी पर विचार चल रहा है। इसके तहत कंपनियों को खाली बोतल और पाउच आदि के दाम प्रिंट करना होगा। इससे लोग खाली बोतलों आदि को फेंकेंगे नहीं बल्कि उसे दुकानदार को लौटाएंगे। हालांकि इस योजना पर अभी विचार चल रहा है। ऐसा ही प्रयोग महाराष्ट्र ने भी शुरु किया था, उनसे भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही कुछ निर्णय लेंगे।
>
> **अनुपम राजन,** चेयरमेन पीसीबी

दैनिक जागरण 8/9/18

पीसीबी के साथ स्वीडन के वैज्ञानिकों ने देखी कारखानों की स्थिति

जल और वायु प्रदूषण की स्थिति पर जताया संतोष

मंडीदीप। नगर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखानों से हानिकारक वायु और जल प्रदूषण होता है इस को लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पीसीबी के वैज्ञानिक लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत गुरुवार को पीसीबी की टीम ने इंडस्ट्रीयल एरिया की कंपनियों का विजिट किया। इस दल में स्वीडन देश के भी चार.वैज्ञानिक शामिल रहे। जानकारी देते हुए पीसीबी के अधिकारी डॉ. नीरज वर्मा ने बताया की उनके यहां वैज्ञानिकों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। इसमें भोपाल एवं इंदौर के साथ प्रदेश के अन्य बोर्ड के करीब 40 वैज्ञानिक शामिल है । ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ही टीम मंडीदीप की ल्युपिन और एचईजी कंपनी में विजिट करने गई थी । इस टीम में स्वीडन देश की सेपा स्वीडिश एनवायरमेंटल प्रोटेकशन एंजेसी के चार वैज्ञानिक भी शामिल हुए। डॉ. वर्मा ने बताया कि पीसीबी ने जल प्रदूषण के मामले में ल्युपिन और वायु प्रदुषण में एचईजी को मॉडल माना है। इसी आधार पर टीम को इन कंपनियों का विजिट कराया। विदेशी वैज्ञानिकों ने ल्युपिन में जल प्रदूषण और एचईजी कंपनी में वायु प्रदूषण के मानक स्तर को परखा। इस पर स्वीडन वैज्ञानिकों ने संतुष्टी जताई।

पत्रिका 5/9/18

प्रदूषण नियंत्रण की अत्याधुनिक तकनीकों पर प्रशिक्षण देंगे स्वीडन के विशेषज्ञ

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. देश में औद्योगिक प्रदूषण की बेहतर मॉनिटरिंग और नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वीडन के विशेषज्ञों से आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम पर काम कर रहा है। कार्यक्रम के पहले चरण में मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभागार में चार दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इसमें स्वीडन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के विशेषज्ञों के साथ सीएसई (सेंटर फॉर एनवायरमेंट) एवं देश के 10 राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।

पर्यावरण मंत्री अंतर सिंह आर्य ने उद्घाटन किया। पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने प्रदेश के प्रदूषणकारी उद्योगों पर स्थापित ऑनलाइन मनिटरिंग सिस्टम की जानकारी दी। स्वीडन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के बो जानसन ने बताया कि स्वीडन में अपनाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण कानून, उसके स्तर, पालन और निरीक्षण से भारत के विशेषज्ञ परिचित हो सकेंगे। आइडिया एक्सचेंज से दोनों देशों को लाभ पहुंचेगा। स्वीडन के विशेषज्ञ एवं भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि बुधवार को मंडीदीप में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का निरीक्षण करेंगे।

नई दुनिया दि. 5/09/2018

उखड़ी सड़कें व कोल बेस्ड पावर प्लांट के कारण भारत की हवा स्वीडन से खराब

राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वीडन के पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

भारत की हवा स्वीडन से ज्यादा खराब है। इसकी मुख्य वजह कच्ची व उखड़ी हुई सड़कें व कोयले से चलने वाले पावर प्लांट हैं जो हवा में धूल के कण घोल रहे हैं। स्वीडन की हवा बहुत हद तक साफ है। केवल नाइट्रोजन आक्ससाइड का खतरा है, जिसका स्तर कम करने के लगातार प्रयास चल रहे हैं।

भारत चाहे तो कोल बेस्ड प्लांट को खत्म कर सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। यह बात स्वीडिश एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के विशेषज्ञ बो जॉनसन ने कही। वे भोपाल में चल रही राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं। प्रशिक्षण मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में 4 सितंबर से शुरू हुआ है जो 7 सितंबर तक चलेगा। इसमें अलग-अलग राज्यों के प्रदूषण नियंण बोर्ड के विशेषज्ञ भी हिस्सा ले रहे हैं। बो जॉनसन स्वीडिश एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार हैं। उन्होंने बताया कि मप्र समेत सभी जगह पीएम का स्तर अधिक है। इसका कारण कच्ची सड़कें व उखड़ी हुईं सड़कों से पर्यावरण में धूल के कणों का होना है। मप्र में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट हैं। वे सभी हवा को दूषित कर रहे हैं। उन्होंने कार्यशाला में भी इस विषय पर चिंता जताई और रोकथाम करने के उपाए बताए।

विशेषज्ञों ने दिए सुझाव

- सौर ऊर्जा का उपयोग करें, कोल बेस्ड प्लांट का विकल्प जल्दी खोजें।
- निकायों से निकलने वाले कचरे को जमीन में मिलने से रोकें, रिसाइकिल कर उपयोग करने की आदत डालें।
- पर्यावरण नियमों का कड़ाई से पालन करें, आम जनता भी सार्वजनिक स्थानों पर रखी डस्टबिन में सेग्रीगेशन के हिसाब से कचरा डालें।

जहां देखो वहां कचरे का ढेर

स्वीडिश एजेंसी के क्लॉस सर्वसन ने कहा कि स्वीडन में 0.7 फीसदी कचरा ही जमीन में मिलने देते हैं। वहीं भारत में जहां देखो वहां जमीन पर कचरे का ढेर मिल जाता है। यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कचरे में कई तरह के केमिकल रहते है जो भूमिगत जल को दूषित करते हैं। आसपास की जमीन बंजर हो जाती है। उन्होंने बताया कि 48.5 फीसदी कचरे को उनके यहां रिसाइकिल कर उर्जा में बदल लेते हैं। 34.6 फीसदी कचरे को रिसाइकिल कर दोबारा उपयोग करते हैं। जबकि 16 फीसदी कचरा बायोलॉजिकल रिसाइकिलिंग में चला जाता है। भारत में ऐसा कम होता है जो चिंता का विषय है।

मंत्री बोले, पौधे लगा रहे हैं

प्रशिक्षण का शुभारंभ पर्यावरण विभाग के मंत्री अंतरसिंह आर्य ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने पौधे लगा रहे है। उद्योगों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग कर हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। नदियों पर पाइंट बनाकर पानी की शुद्धता जांची जा रही है। पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने कहा कि बो जॉनसन व उनकी टीम से पर्यावरण के हित में और अच्छा काम करेंगे। सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट के प्रतिनिधि निवित कुमार ने कहा कि प्रदूशण पर नियंत्रण पाने स्वीडन में अपनाई जा रही तकनीकी को अपनाया जाएगा। बोर्ड के सदस्य एए मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर किस तरह प्रयास किए जा रहे है।

भास्कर सिटी 04/09/2013

प्रदूषण नियंत्रण पर चार दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन आज से

सिटी रिपोर्टर | मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 4 सितम्बर से चार दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सेंटर फॉर साइंस एन्वॉयर्नमेंट और स्वीडन एन्वॉयर्नट प्रोटेक्शन के सहयोग से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्वीडन एन्वायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के हैड बिजासन का व्याख्यान होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का विषय कंप्लायंस मॉनिटरिंग एण्ड एनफोर्समेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया एंड स्वीडन है। कार्यक्रम में स्वीडन एनिमल प्रोटेक्शन एजेंसी के 4 एक्सपर्ट सहित लगभग 50 लोग शामिल होंगे। इसमें भारत तथा स्वीडन में प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की चर्चा होगी।

DB स्टार STAR CITY BHOPAL | TUESDAY 04 SEPTEMBER | 2018

4/9/18

धुआं छोड़ते पुराने कंडम वाहन बढ़ता प्रदूषण, बेपरवाह पीसीबी

नियंत्रण में है पॉल्यूशन

पॉल्यूशन के मामले में भोपाल की स्थिति नियंत्रण में है। वाहनों की फिटनेस जांचना और कंडम वाहनों पर कार्रवाई आरटीओ का काम है।
पीएस बुंदेला, क्षेत्रीय अधिकारी, एमपीपीसीबी

कार्रवाई करना चाहिए

पेड़-पौधे कम होते जा रहे हैं और वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वजह से शहर में वायु प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। समय रहते जिला प्रशासन को पुराने एवं कंडम वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए।
सुनैना जैन, निवासी, शाहजहांनाबाद

डीबी स्टार • भोपाल

शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें अनेक वाहन काफी पुराने और दूसरे राज्यों के हैं, जिनसे अत्यधिक धुआं निकलता रहता है। ऐसे वाहन जहां से निकलते हैं, वहां चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देता है। इस कारण अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके चलते शहर में वायु प्रदूषण फैल रहा है। इस वजह से कई घातक बीमारियां जन्म ले रही हैं। वाहनों में ईंधन के तौर पर डीजल-पेट्रोल के अलावा मिट्टी के तेल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इनसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें निकलती हैं, जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। इस कारण इन गैसों का मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। धुआं छोड़ रहे वाहन हमीदिया रोड, सुल्तानिया रोड, कोलार रोड, शाहजहांनाबाद, डीआईजी बंगला, रायसेन रोड, जेके रोड, होशंगाबाद रोड पर अधिक दौड़ रहे हैं। सरकार को प्रदेश के पुराने और अन्य राज्यों से आने वाले कंडम वाहनों को दुरुस्त कर चलाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल भी इतनी गंभीर समस्या से अंजान बना हुआ है।